दैनिक जागरण

संघर्ष की चाबी जीवन के सभी बंद दरवाजे खोल देती है

## पाकिस्तान के अल्पसंख्यक

पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हमले की घटना को लेकर पाकिस्तान ने वैसी ही लीपापोती की जैसी उसकी आदत है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की मानें तो इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में कहीं कुछ नहीं हुआ। वह इस झूठ के पीछे इसलिए नहीं छिप सकता, क्योंकि इस गुरुद्वारे के सामने जमा हिंसक भीड़ के व्यवहार और उसकी भड़काऊ नारेबाजी को सारी दुनिया ने देखा-सुना है। यदि ननकाना साहिब में कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर वहां घोर आपत्तिजनक नारे क्यों लगे और पत्थरबाजी कौन कर गया? सवाल यह भी है कि इस घटना के अगले दिन वहां के सिखों को नगर कीर्तन निकालने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? पाकिस्तान अपने यहां के उपेक्षित, अपमानित और आतंकित अल्पसंख्यकों की हिफाजत के खोखले दावे कर देश-दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की चाहे जितनी कोशिश करे, हकीकत यही है कि वहां रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई आदि एक तरह से अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। उनका कोई भविष्य नहीं। वे या तो जबरन धर्मांतरण का शिकार होंगे या फिर अपमानित जीवन जीने को विवश होंगे। उन्हें त्रासदी भरे जीवन से तभी छुटकारा मिल सकता है जब वे या तो अपना धर्म छोड़ दें या फिर देश। वास्तव में इसी कारण पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है।

पाकिस्तान के हालात सुधरने की कहीं कोई उम्मीद इसलिए नहीं, क्योंकि एक तो कट्टरपंथी तत्व सेना एवं सरकार से संरक्षित हैं और दूसरे, ईशनिंदा सरीखा दमनकारी कानून अस्तित्व में है। जब तक यह कानून अस्तित्व में रहेगा, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की जान सांसत में ही बनी रहेगी। ननकाना साहिब की घटना के बाद भारत में उन लोगों की आंखें खुल जाएं तो बेहतर जो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून का अंध विरोध करने में लगे हुए हैं। आखिर पाकिस्तान में सताए जा रहे हिंदू, सिख आदि भारत की ओर नहीं निहारेंगे तो क्या अमेरिका, कनाडा से उम्मीद लगाएंगे? कम से कम अब तो नागरिकता कानून के विरोधियों को उसके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने से बाज आना चाहिए, क्योंकि इस कानून के जरिये पाकिस्तान और साथ ही बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यदि आपत्ति इस पर है कि इस कानून का लाभ इन तीनों देशों के उन अल्पसंख्यकों को ही मिलने जा रहा है जो दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके है तो फिर विपक्ष को ऐसी कोई मांग करनी चाहिए कि इस समय सीमा को बढ़ाया जाए। क्या वह ऐसा कर रहा है? क्या यह किसी से छिपा है कि वह इस कानून को सिरे से खारिज किए दे रहा है?

## सर्दी में सुरक्षा

सतर्कता बरती जाए तो किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। एक छोटी से भूल किसी बड़े हादसे का कारण भी बन जाती है। मौसम कोई भी हो, आग लगने की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। यह सही है कि आग लगने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन कई बार मानवीय चूक के कारण भी अग्निकांड हो जाते हैं। ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के हरिपुर में सामने आया है। यहां एक शिक्षक की झुलसने से मौत हो गई। इसी तरह पालमपुर में भी लोक निर्माण विभाग के चौकीदार की मौत हुई है। हालांकि अभी तक दोनों हादसों के कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन प्रारंभिक जांच में हीटर से बिस्तर को आग लगना ही कारण बताया जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। ठंड से बचने के लिए लोग अंगीठी व हीटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अंगीठी की गैस लगने से भी मौत के मामले भी सामने आते रहे हैं। यह सही है कि आपदा को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन सतर्कता से नुकसान को कम किया जा सकता है। रात को सोते समय यदि हीटर को बंद कर दिया जाए या अंगीठी को आग बुझने के बाद कमरे से बाहर खुली जगह में रख दिया जाए तो आग लगने या अंगीठी की गैस लगने की आशंका नहीं रहती है। सर्दियों में आग लगने की भी घटनाएं प्रदेश में सामने आती रहती हैं। कई बार आग लगने के कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट भी होता है, लेकिन आग लगने के और भी कई कारण होते हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल में घरों के निर्माण में लकड़ी का अधिक प्रयोग होता है। कई जगह तो लकड़ी के ही घर बने होते हैं। इन घरों में आग से हमेशा सावधान रहना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बर्फबारी व बारिश के दौरान आग जलाने के लिए लकड़ियों व पशुओं के लिए चारे का भंडारण किया होता है। यहां पर एक छोटी सी भूल बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोग हमेशा सतर्क रहें। आग इत्यादि से निपटने के लिए घरों में पूर्व में प्रबंध किए जाने चाहिए। घरों की वायरिंग इत्यादि की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए। बच्चों सहित सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि आग लगने पर सबसे पहले बिजली का मेन स्विच बंद किया जाए व आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है।

**एक छोटी सी भूल बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और आग इत्यादि से निपटने के लिए पूर्व में प्रबंध करें**

# दोहरी चुनौतियों से दो-चार सरकार

संजय गुप्त

**मोदी सरकार के सामने चुनौती केवल आर्थिक माहौल को दुरुस्त कर कारोबार जगत को उत्साहित करने की ही नहीं, बल्कि राजनीतिक माहौल को सामान्य बनाने की भी है**

अवधेश राजपूत

नए साल में भाजपा को आगे की अपनी राह तय करने के साथ ही बीते साल के अपने सफर पर भी गौर करना चाहिए। ऐसा करते समय वह यही पाएगी कि यह कालखंड उसके लिए मिली-जुली सफलता का रहा। जहां शुरुआती छह माह तो उसकी तूती बोलती रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसने तमाम आकलन को धता बताते हुए भारी-भरकम जीत के साथ दूसरी पारी शुरू की वहीं पारी शुरू करने के कुछ समय बाद ही उसके सामने एक के बाद एक चुनौतियां खड़ी होने लगीं। पहली चुनौती आर्थिक मोर्चे पर उभरी। अर्थव्यवस्था में गिरावट ने आर्थिक सुस्ती का रूप ले लिया। इसके बाद भाजपा को राज्य विधानसभा चुनावों में अपेक्षित नतीजे नहीं मिले। उसने हरियाणा को तो जैसे-तैसे बचा लिया, लेकिन शिवसेना की दगाबाजी से महाराष्ट्र को खो दिया। इसके बाद झारखंड में भी वह अपनी सरकार नहीं बचा सकी।

ऐसा तब हुआ जब मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही तीन तलाक संबंधी कानून को अंतिम रूप देने और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए को खत्म करने में सफल रही। इसमें दो राय नहीं कि इन दोनों बड़े फैसलों से मोदी सरकार एक सशक्त सरकार के रूप में उभरी। हालांकि इसी समय उसे सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन से एक बड़ा आघात लगा। वह इस आघात से उबर पाती कि अरुण जेटली का निधन हो गया। हालांकि खराब सेहत के चलते इन दोनों नेताओं ने खुद को चुनाव से दूर रखा और मंत्रिपरिषद में भी शामिल नहीं हुए, फिर भी वे भाजपा और सरकार के लिए एक बड़ी ताकत थे। अरुण जेटली तो खराब सेहत के बाद भी संकटमोचक की भूमिका निभा रहे थे। उनकी जगह वित्त मंत्रालय का कार्यभार निर्मला सीतारमण ने संभाला और वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनीं। उनके पहले बजट से आम आदमी और कॉरपोरेट जगत को निराशा ही अधिक हाथ लगी। यह निराशा तब और बढ़ गई जब आर्थिक सुस्ती गहराने लगी। इस आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने एक के बाद एक कई फैसले लिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का, लेकिन ये सभी फैसले उद्योगपतियों का भरोसा बढ़ाने में सहायक नहीं साबित हुए।

देखना है कि उनके दूसरे बजट से क्या सूरत बनती है? उन्होंने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। उद्योगपतियों की समस्याओं को जानने के लिए वित्त मंत्री के साथ-साथ खुद प्रधानमंत्री भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वह इन मुलाकातों में और अन्यत्र भी इस बात को लगातार रेखांकित कर रहे हैं कि अगले पांच वर्षों में देश पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लगातार कम से कम आठ-नौ फीसद सालाना की दर से चलना होगा।

यदि इस समय हम कारोबारियों के साथ आम आदमी की मनोदशा देखें तो कोई भी इस लक्ष्य को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखता। जहां आम उपभोक्ता तमाम आशंकाओं से घिरे होने के कारण खुलकर खर्च करने को तैयार नहीं वहीं उद्योगपति भी निवेश करने से बच रहे हैं। इस सबके बीच सरकार कर चोरों पर लगातार सख्ती करती चली जा रही है। कुछ क्षेत्रों में तो यह सख्ती बढ़ती भी दिख रही है। समस्या यह है कि इस सख्ती को लेकर यह दुष्प्रचार हो रहा है कि सरकार उद्योगपतियों को बेवजह परेशान कर रही है। यह वह स्थिति है जो कारोबार जगत का मनोबल बढ़ाने वाली नहीं कही जा सकती, जबकि आज यह आवश्यक है कि उद्योग-व्यापार जगत उत्साहित दिखे। शायद सरकार भी असमंजस में है कि वह कारोबारियों का मनोबल किस तरह बढ़ाए? आज जब उद्योगपति सरकार से राहत और रियायत की तमाम उम्मीदें कर रहे हैं तब उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि यह सरकार दो नंबर के तौर-तरीके सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वह उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त है। प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह इस प्रतिबद्धता को बार-बार प्रकट भी करते हैं। इस स्थिति में किसी को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट तौर-तरीकों के लिए कोई गुंजाइश बनने देंगे। साफ है कि कारोबार जगत को यह समझना होगा कि पुराने तौर-तरीके चलने वाले नहीं हैं और उसे साफ-सुथरे तरीके अपनाने ही होंगे।

मोदी सरकार के सामने चुनौती केवल यही नहीं कि वह आर्थिक माहौल को दुरुस्त कर कारोबार जगत को उत्साहित करे, बल्कि यह भी है कि राजनीतिक माहौल को भी ठीक करे। इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून, नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी और जनसंख्या रजिस्टर अर्थात एनपीआर को लेकर विपक्षी दलों ने एक भ्रम का माहौल बना रखा है। सरकार के तमाम स्पष्टीकरण के बाद भी विपक्षी दल लोगों को बहकाकर सड़कों पर उतारने में लगे हुए हैं। वे दुष्प्रचार का सहारा लेकर राजनीतिक और साथ ही सामाजिक माहौल में भी कलह घोलने का काम रहे हैं। यह ठीक है कि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह नागरिकता कानून पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी, लेकिन शायद केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। उसे उन कुतर्कों और भ्रम की काट भी करनी होगी जो विपक्षी दलों ने जनता के एक वर्ग के बीच फैला रखा है। इस वर्ग को उन तमाम गुटों का भी समर्थन मिल रहा है जो किसी न किसी कारण सरकार के विरोधी हैं और उससे अपना हिसाब चुकता करने के फेर में हैं। विपक्षी दल और साथ ही सरकार से असंतुष्ट तमाम गुट यह समझने से इन्कार कर रहे हैं कि वे समाज में भ्रांति फैलाकर टकराव की नींव रख रहे हैं। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि विपक्षी दल और अन्य तत्व समाज में कलह न पैदा करने पाएं, क्योंकि अब यह अंदेशा भी बढ़ रहा है कि कई अतिवादी गुट भी जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं।

सरकार को चाहिए कि वह नागरिकता कानून को लेकर आम लोगों तक पहुंच बढ़ाए ताकि वे और अधिक भटकाव का शिकार होने के साथ ही शरारती तत्वों के हाथों में खेलने से बच सकें। उसे आम लोगों और खासकर नागरिकता कानून और एनपीआर को लेकर भ्रम के शिकार लोगों को यह समझाना ही होगा कि इनके पीछे उद्देश्य क्या है? इसी के साथ उसे आर्थिक माहौल को सुधारने को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक हालात में सुधार के उपाय जमीन पर असर करते हुए भी दिखें। ऐसा करके ही देश को पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

response@jagran.com

# बड़े काम की साबित होती नेटबंदी

हास्य-व्यंग्य

सूर्यकुमार पांडेय

**जब-जब इंटरनेट बंद रहा तब-तब अनचाहे और अनावश्यक संदेश पढ़ने से जो फुरसत मिली उसने बड़ी राहत दी**

इंटरनेट का करिश्मा इंद्रजाल के जादू की भांति हम सबके सिरों पर चढ़कर अपने खेल दिखा रहा था। इसके चलते हम एक आभासी दुनिया में रहने लगे और अपने यथार्थ और परिवेश से कटते जा रहे हैं। इस इंटरनेट ने हमारे हाथों में एक डिब्बेनुमा खिलौना पकड़वा रखा है, जिसमें हम सगर्व अपना सिर झुकाए उसे थामे हुए देखे जा सकते हैं। यह अलग बात है कि हमारे शास्त्रों में सिर झुकाकर चलने को विनम्रता का प्रतीक बताया गया है। अगल-बगल की ताकझांक अशिष्टता की द्योतक होती है, लेकिन समय बदला और जब हमने नेटयुक्त मोबाइल युग में प्रवेश किया तो जिस गर्दन को तनना था, वह झुकने लग गई। अंगुलियां सदा चलायमान हो गईं और हमारी आंखें मोबाइल स्क्रीन की दीवानी हो गईं। इधर हाल के दिनों में इस यथास्थिति में किंचित व्यवधान आया है। इस अवस्था को नेटबंदी कहा जाने लगा है।

'संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं' की लत का शिकार हो चुके लोगों को भले ही इंटरनेट के चालू होने और बंद होने से फर्क पड़ता हो, लेकिन मनुष्य की सोच सकारात्मक होती है तो वह दुख के दिनों में सुख का अनुभव कर सकता है और हर्ष-विषाद में भी समभाव से रह सकता है। अपन को तो इस नेटबंदी के कई फायदे दिखलाई दे रहे हैं। अगर हाल के दिनों की नेटबंदी से मायूस होकर आप इन फायदों को न देख-समझ पाए हों तो चिंता की बात नहीं। मैं उन्हें गिनाना शुरू करता हूं।

रोजाना मुझे प्रतिदिन पचीस-पचास लोग वॉट्सएप के जरिये 'सुप्रभात' और 'शुभ दिन' टाइप के संदेश भेजते हैं। वह दीगर बात है कि मैं कभी इन संदेशों को शाम तक देख पाता हूं और कभी एक-दो दिनों के अंतराल पर। इतना ही नहीं, इनके प्रत्युत्तर तो मैं कतई नहीं दिया करता। जब-जब नेटबंदी हुई तो अनचाहे संदेश पढ़ने से जो फुरसत मिली वह बड़ी राहत भरी रही। वैसे लगता नहीं कि ऐसे संदेश भेजने वालों की कर्मनिष्ठा में कोई कमी आएगी। ऐसे लोग सतत अपना कर्म करने में विश्वास करते हैं, उन्हें फल की आकांक्षा या कोई आशा भी नहीं होती। इन्हें मैं निष्काम कर्मयोगी कहा करता हूं। इनमें से कोई दिन में टकरा भी जाता है, लेकिन क्या मजाल कि अगला सिर उठाकर अभिवादन ही कर ले या मेरा अभिवादन स्वीकार कर ले, क्योंकि वह सड़क पर चलता भी है तो मोबाइल स्क्रीन में लीन रहता है।

कुछ लोग मैसेजिंग में मसाजिंग का सुख पाते हैं और तरोताजा होने का सुख उठाते हैं। कई लोग सवेरे-सवेरे उगते हुए सूर्य की तस्वीरें भेजते हैं। मुझे इन पर हंसी आती है। इस जाड़े में जहां एक ओर सूर्यग्रहण भी लगता है, तो भी दिखलाई नहीं पड़ता और अगले को धुंध-कोहरे में भी ऐसी तस्वीर भेजने से परहेज नहीं है। अब क्षणिक ही सही, नेटबंदी हुई, तो दो-चार लोगों से दुआ-सलाम की नौबत आई। इसका निष्कर्ष और लाभ यह है कि नेटबंदी से सामाजिकता बढ़ती है। कहने को तो इंटरनेट पर सोशल मीडिया का बोलबाला है, लेकिन वह उतना ही अन-सोशल भी होता जा रहा है। कुछ की नजर में तो सोशल मीडिया दरअसल एंटी सोशल है।

नेटबंदी का दूसरा और प्रत्यक्ष लाभ यह है कि प्रत्येक नेट उपभोक्ता में एक अलग तरह की तत्परता आ जाती है। वह सदैव आशंकाग्रस्त रहता है कि जाने कब नेट चला जाएगा और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप आदि की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, इस नाते जो बात कल की जा सकती है, उसे वह आज ही कर डालता है। इस तरह वह 'काल करे सो आज कर, आज करे सके सो अब' की शाश्वत नीति का अनुपालन करने लग जाता है। नेटबंदी का यह फायदा भी कम काबिलेगौर नहीं है कि इससे हमें भांति-भांति की इमोजी के दर्शन और वीडियो गेम्स से कुछ वक्त के लिए निजात मिल जाती है। नेट यूजर्स को वायरल वीडियोज के बुखार में राहत का अनुभव भी होता है।

नेटबंदी संवेदनशील समय में अफवाहों के मुंह पर तालाबंदी का काम करती है। इतना ही नहीं, यह गूगल बाबा के जरिये हासिल अधकचरे ज्ञान से बचाव का भी कारगर उपाय है। और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इस दौरान ऑनलाइन ठगी करने वाले भी स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उम्मीद है कि अब आप भी यह मानेंगे कि नेटबंदी बड़े काम की है।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

**सेहत पर खर्च** (राज्यों के कुल बजट में स्वास्थ्य पर खर्च का प्रतिशत)

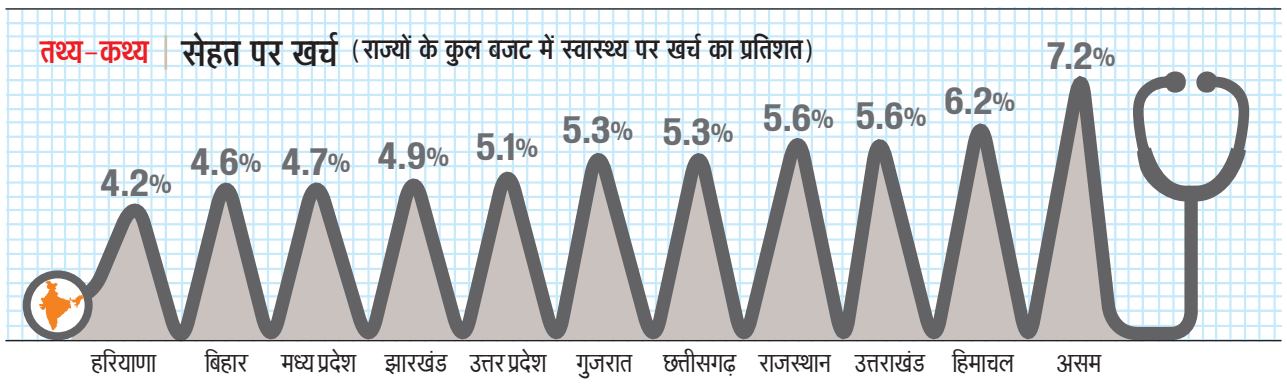


ऊर्जा

## शब्दों की शक्ति

नववर्ष के भी कुछ दिन गुजर गए हैं। इस दौरान शुरुआत में लिए गए कई संकल्पों ने भी दम तोड़ दिया होगा। आखिर हर साल की यही कहानी क्यों होती है? इससे निपटने के लिए अगर हम इच्छाशक्ति के साथ ही शब्दों की ताकत का भी संज्ञान लें तब बात बन सकती है। बार-बार संकल्पों को लेकर निराशा के भाव से पीड़ित लोग अक्सर कठोर रणनीति अपना लेते हैं। इस कारण वह स्वयं के शत्रु बन जाते हैं। ये स्वजनित शत्रु संकल्पों की सिद्धि में और अवरोध ही उत्पन्न करते हैं। ऐसे में इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए इस वर्ष कठोर बनने के बजाय शब्दों का प्रयोग कर लचीला बनना सीखें। स्मरण रखें कि सकारात्मक और रचनात्मक नीति हर विपरीत परिस्थिति को सहज बनाकर हमारी राह आसान बना देती है।

सकारात्मक सोच की रणनीति में यदि लचीले शब्द डाल दिए जाएं तो फिर भंगुर लोहा भी टूट जाता है। कोई विपदा भी ऐसे व्यक्ति को तोड़ नहीं सकती। इसलिए अपने शब्दों पर गौर करें और उन्हें बदलने का प्रयत्न करें। यदि लोग आपके शब्दों से नाराज हो जाते हैं, आपके काम बिगड़ जाते हैं तो तुरंत लचीले शब्दों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। हर स्थिति में मतभेद से कार्य बिगड़ जाते हैं, इसलिए मतभेद के बजाय सहमति एवं मन मिलाने का प्रयत्न करें।

अक्सर हम देखते हैं कि अनेक विवाद केवल शब्दों के हेरफेर से पनपते हैं और हैरानी की बात यह है कि तमाम विवादों का अंत भी केवल समझदारी भरे शब्दों का चयन करके ही किया जा सकता है। समझदारी भरे कुछ शब्द अपने सामने रखिए। नए वर्ष में उनका प्रयोग करने की आदत डालिए। धीरे धीरे ये नए शब्द कुछ ही समय में आपकी किस्मत और व्यक्तित्व को बदल देंगे और आप एक चमत्कारी व्यक्तित्व बनकर उभरेंगे। तब फिर क्यों न आज से ही सकारात्मक और लचीले शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया जाए ताकि नववर्ष पर ये शब्द आपकी दिशा को सही राह पर ले जाएं और आपको प्रारंभ में ही सफलता की ओर बढ़ाएं।

रेनू सैनी

# निचले पहाड़ी इलाकों पर खतरा

मुकुल व्यास

**कई हिमालयी झीलों के तटबंध टूटने से मानव बस्तियों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बहुत नुकसान पहुंचेगा**

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय की हजारों बर्फीली झीलें अपने तटबंध तोड़कर निचली नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकती हैं। वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटरीकृत मॉडल से पता लगाया है कि बर्फ पिघलने से झील का पानी धीरे-धीरे ढीली चट्टानों और मिट्टी के अवरोधों को तोड़कर आगे बढ़ेगा। इन मॉडलों से पता चलता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में करीब पांच हजार झीलें अपने तटबंधों की कमजोरी के कारण अस्थिर हैं। ये तटबंध बिखरी हुई चट्टानों और मिट्टी से बने हैं। यदि ये अवरोध टूट जाएंगे तो नीचे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाएगी जो पहाड़ के तल पर रहने वाले लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है।

यह अध्ययन जर्मनी की पोस्टडैम यूनिवर्सिटी के सहयोग से हुआ है। इसमें भौगोलिक आंकड़ों और उपग्रहों के आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए झीलों के मॉडलों का विस्तार से अध्ययन किया। यदि पांच हजार झीलें अपने अवरोध तोड़ घाटी के नीचे बहती हैं तो बाढ़ आएगी ही। शोधकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि इन झीलों में पानी की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। इन बर्फीली झीलों से उत्पन्न होने वाली बाढ़ का खतरा हिमालय के पूर्वी हिस्सों में तीन गुना अधिक है। इस चौंकाने वाली खोज के साथ ही विशेषज्ञों ने पिछले अध्ययनों के बारे में ध्यान दिलाया जिनमें कहा गया है कि हिमालय के दो-तिहाई ग्लेशियर अगले दशक में गायब हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन झीलों में अत्यधिक मात्रा में पानी के जमाव से घाटी के नीचे रहने वाली आबादियों, बुनियादी ढांचों और पनबिजली परियोजनाओं के समक्ष गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा।

गत वर्ष जून में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक पृथक अध्ययन से पता चला था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान वृद्धि से पिछले दो दशकों में हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की दर दोगुनी हो गई है। बढ़ते तापमान से इस क्षेत्र में हर वर्ष कम होने वाले पानी की मात्रा 32 लाख ओलंपिक तरणतालों के पानी के बराबर है। इस सदी की शुरुआत के बाद हिमालय के ग्लेशियरों में हर साल 51 सेंटीमीटर बर्फ कम हो रही है। भारत, चीन, नेपाल और भूटान में पिछले 40 वर्षों के दौरान किए गए उपग्रह पर्यवेक्षणों पर आधारित इस अध्ययन से पता चला कि बर्फ का पिघलना नियमित रूप से हो रहा है और इसके लिए तापमान-वृद्धि ही दोषी है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और पृथ्वी के गर्म होने से सिर्फ हिमालय के ही नहीं, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं।

इन पिघलने वाले ग्लेशियरों से समुद्रों में जल स्तर बढ़ रहा है जिसकी वजह से समुद्री तटों के क्षरण का खतरा पैदा हो गया है। आने वाले समय में शंघाई से लेकर लंदन जैसे अनेक शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया में सभी जगह ऐसे प्रभाव एक जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन जोखिम वाले क्षेत्रों में अमेरिकी संपत्तियों के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2045 तक तीन लाख घर जलमग्न हो सकते हैं जो बहुत चिंताजनक है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

### एक तीर से दो निशाने

उन्हें देश का बेहतरीन सांख्यिकीविद बताया जाता है। गरीबी, रोजगार और आमदनी इत्यादि के आंकड़ें कैसे जुटाए जाएं, इसे उनसे बेहतर बहुत ही कम लोग शायद कर पाएं। वह मौजूदा सरकार से खफा भी रहते थे कि वह आंकडों को जुटाने को लेकर गंभीर नहीं है और इस बारे में जो कदम उठा रही है वह सही नहीं है। अब सरकार ने उन्हें आंकड़े जुटाने की नई समिति की जिम्मेदारी सौंपकर एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। एक तो उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया गया जो यह कहते नहीं थकते कि सरकार को विरोधी विचारधारा के लोग फूटी आंख नहीं सुहाते और दूसरा यह कि देश में बेहतरीन व पारदर्शी तरीके से आंकड़े जुटाने का काम भी हो जाएगा।

### अधूरी रह गई आस

बड़ी आस लगाए बैठे थे, लेकिन बुलावा ही नहीं आया। भला ऐसे में वहां कैसे पहुंचते जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक शिरकत करने पहुंचे हैं। यहां बात बेंगलुरु की हो रही है, जहां नेशनल साइंस कांग्रेस का शानदार पंडाल सजा है। वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभूतियां नित नया ज्ञान परोस रही हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में बैठे वैज्ञानिक बड़े मायूस हैं। इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम 'साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया' है। इसमें दिलचस्प बात यही है कि जो वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें बुलावा ही नहीं भेजा गया। ग्रामीण क्षेत्र में खेती-किसानी की उपयुक्त टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन इस दिशा में काम करने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर के वैज्ञानिक आयोजन में नहीं पहुंचे हैं। यह जलसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के परिसर में हो रहा है। वहीं इसमें लंबा-लंबा भाषण देने के सपने संजोने वालों को मायूसी ही हाथ लगी।

### साहब सावधान, मातहत परेशान

केंद्र में पहली बार मंत्री बनकर आए एक साहब द्वारा अलसुबह की रिपोर्टिंग खासी चर्चा में है। उनके साथ काम करने वाले अफसर उनकी इस आदत से बहुत परेशान हैं। बताते हैं कि बड़े साहब को लंबे समय से सुबह पौने पांच बजे उठने की आदत है। स्थिति यह है कि रात में वह भले ही कितने बजे ही सोएं, लेकिन सुबह तय समय पर उठने से नहीं चूकते। इसके बाद तो उनके फोन मातहतों के मोबाइल पर घनघनाने लगते हैं। जबकि दिल्ली की आबोहवा में रचे बचे अधीनस्थ उस समय तक नींद में ही होते हैं। ऐसे में बड़े साहब का फोन उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस मुश्किल से बचने के लिए अफसरों को अपनी देर रात की पार्टी व सैर-सपाटे की आदत से तौबा करनी पड़ रही है। फिर भी बड़े साहब का टाइम नहीं पकड़ पा रहे हैं।

### संकोची नड्डा

यूं तो बड़े राजनीतिक दलों के छुटभैये नेताओं में भी बहुत ठसक होती है और उनकी यही कोशिश होती है कि वे जहां जाएं वहां वीआइपी की तरह ही ट्रीट किए जाएं। सत्तारूढ़ दल के नेताओं में ऐसी हसरतें और ज्यादा होती हैं, लेकिन बहुत जल्द भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा इतने संकोची हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले यह सुनिश्चित करने में जुट जाते हैं कि उनके कार्यक्रम से किसी दूसरे को कोई असुविधा न हो। झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान वह देवघर के वैद्यनाथ धाम में पूजा के लिए जाना चाहते थे, लेकिन यह संशय था कि जाएं या न जाएं, कहीं भक्तों की भीड़ को रोकने से ऐसी स्थिति न पैदा हो कि कोई आवाज उठे। लिहाजा नड्डा के सहयोगियों ने स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे को यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसा प्रबंध किया जाए कि भीड़ को ज्यादा असुविधा न हो और नड्डा के लिए असहज स्थिति न पैदा हो।

इसके बाद जो इंतजाम किए उनमें नड्डा ने फटाफट पूजा-अर्चना की और बाहर आ गए।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।